



Neutral Citation No.- 2026:AHC:128964

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 23955 वर्ष 2026

श्रीमती कमलू नीशा एवं अन्य

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता: मोहम्मद नौशाद

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: मु.स्था.अधि.

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादीगणके लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:

"(i) प्रतिवादी संख्या 2 तथा 3 को याचिकाकर्तागण को प्रतिवादी संख्या 4 से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने वाली परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिससे वह दोनों याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न कर सके।

(ii) प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह माननीय न्यायालय जो उचित एवं उपयुक्त समझे, ऐसी कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(iii) याचिकाकर्तागण को याचिका का व्यय प्रदान किया जाए।"

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दोनों याचिकाकर्तागण वयस्क हैं तथा यद्यपि याचिकाकर्तागण के बीच विवाह पर उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आपत्ति थी, उन्होंने दिनांक 05.06.2026 को विवाह किया। तथापि, परिवार के सदस्य याचिकाकर्तागण को लगातार परेशान कर रहे हैं तथा उनके वैवाहिक सामंजस्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं; और इसलिए, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित

अपने जीवन तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा चाहते हुए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधीन इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की है।

4. **ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक नारी निकेतन दिल्ली एवं अन्य, 1976 3 SCC 234** में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तियों की पीठ ने यह धारित किया था कि यदि कोई लड़की वयस्क है, तो उस व्यक्ति की उसकी पसंद पर, जिसके साथ वह रहना चाहती है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, न ही उस स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहां उसे रहना चाहिए; तथा यदि वह 18 वर्ष से अधिक आयु की है, तो वह सुई ज्यूरिस (स्वाधिकारी) है। रिश्तेदार ऐसे प्रकरण में याचिकाकर्ता की राय या पसंद के स्थान पर अपनी राय या पसंद को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।

5. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 5 SCC 475** में सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर-जातीय विवाहों पर भी विचार किया तथा उनका स्वागत किया और यह धारित किया कि एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। उक्त निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायमूर्तियों की पीठ ने **एस. खुशबू बनाम कन्नियमल एवं अन्य, 2010 5 SCC 600** में भी बरकरार रखा; तथा यह धारित किया कि एक वयस्क लड़की जिससे चाहे उससे विवाह करने या "जिसके साथ चाहे उसके साथ रहने" के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि सामाजिक नैतिकता की धारणा स्वाभाविक रूप से व्यक्तिनिष्ठ है तथा दांडिक विधि का उपयोग व्यक्तिगत स्वायत्तता के क्षेत्र में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता। नैतिकता तथा अपराधिकता समान विस्तार वाली नहीं हैं **(संदर्भ: नंद कुमार एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य, 2018 16 SCC 602)**।

6. प्रकरण के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि दोनों याचिकाकर्तागण वयस्क हैं तथा वर्तमान रिट याचिका के साथ दाखिल शपथ पत्र याचिकाकर्तागण के संयुक्त शपथ पत्र के माध्यम से है और राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता भी इस तथ्य का खंडन नहीं करते कि दोनों याचिकाकर्तागण वयस्क हैं; और इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका को स्वीकृति चरण में ही निस्तारित किया जा रहा है; लेकिन तथापि यदि वर्तमान रिट याचिका के साथ दाखिल शपथ पत्र में कहे गए किसी भी तथ्य को गलत पाया जाता है, तो प्रतिवादीगण के लिए एक रिकॉल दाखिल करना उपलब्ध होगा।



(i) याचिकाकर्तागण एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं तथा यदि कोई भी व्यक्ति उनके वैवाहिक जीवन या शांतिपूर्ण रहन-सहन में हस्तक्षेप करता है, तो याचिकाकर्तागण इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो याचिकाकर्तागण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

(ii) इस तथ्य के दृष्टिगत कि याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के अनुसार, कोई प्र.सू.रि. या शिकायत दर्ज नहीं की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश किसी भी प्रकार से विवाह की वैधता या विवाह प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की वास्तविकता के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करता है।

7. उपर्युक्त टिप्पणी तथा निर्देश के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन)

24 जून, 2026

पीयूष